राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

विधानसभा में राज्यपाल का स्वागत

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विधानसभा में अभिभाषण दिया

जयपुर, 19 जनवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने शुक्रवार को सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया।

इससे पहले राज्यपाल श्री मिश्र के विधानसभा में प्रातः 11 बजे पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव ने स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल श्री मिश्र को आरएसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई। बाद में राज्यपाल श्री मिश्र को अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेशन में ले जाया गया।

इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना का सदन के सभी सदस्यों को वाचन करवाया और बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया।

——

संलग्न – माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अविकल रूप में।

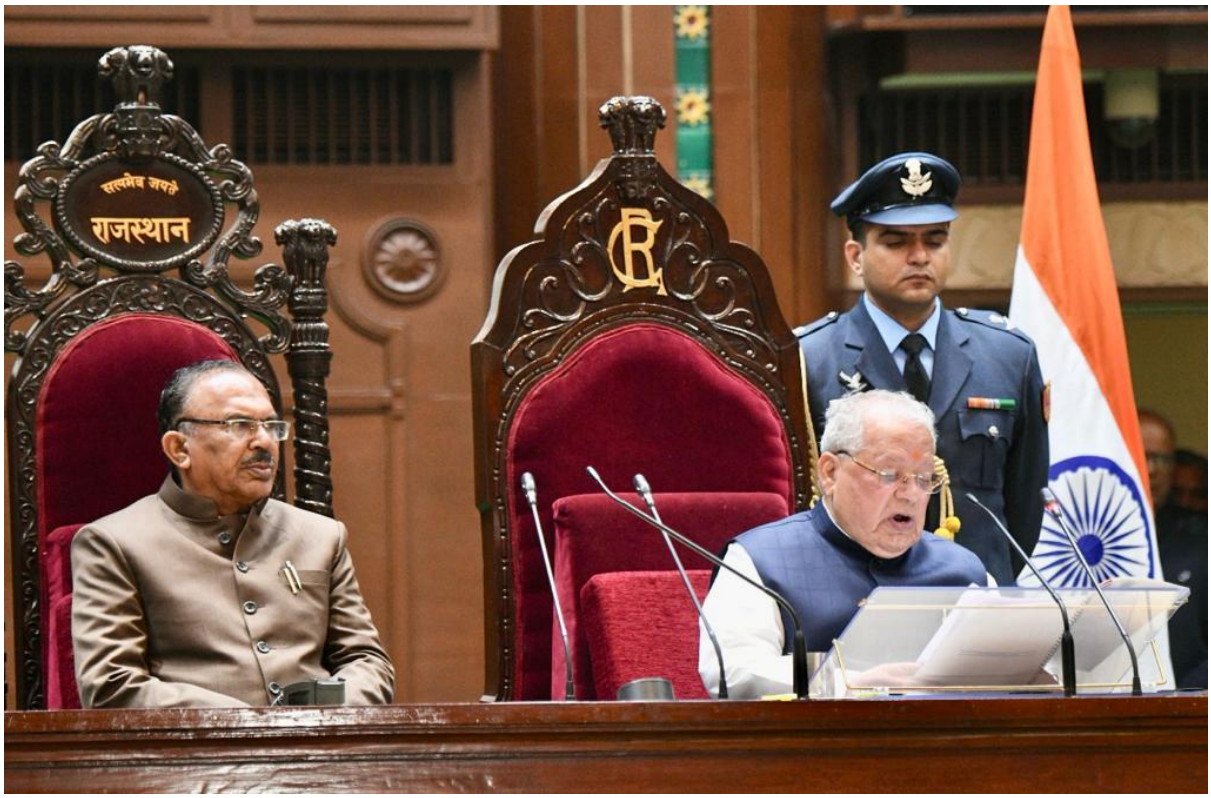
सत्यमेव जयते
राजस्थान

राजस्थान

महामहिम राज्यपाल अभिभाषण जनवरी 2024

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में हुए राज्य की सोलहवीं विधानसभा के चुनाव निर्विघ्न, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए। मैं प्रदेश की जनता को इस चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान एवं प्रचण्ड बहुमत के साथ जनादेश देने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

1. मैं समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से रख कर, प्रदेश के सर्वांगीण एवं चहुंमुखी विकास में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

2. मैं समस्त माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूँ तथा सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

3. राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन परम्परा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय–समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का सन्देश देते रहे हैं। इस बार भी राजस्थान के आवाम ने 75.45 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान कर एक अनूठा कीर्तिमान रचा जो परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का अनुपम कार्य है।

4. प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़–चढ़ कर भाग लिया और **'राष्ट्र प्रथम'** के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अन्तर्विरोधों एवं अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई, फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी।

5. दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर्विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर ना केवल **नये राजस्थान का निर्माण** करेगी अपितु **विकसित राजस्थान व विकसित भारत 2047** के संकल्प को साकार करेगी। **सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास और सबका प्रयास** हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा।

6. राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटियों** पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा लिए गए इस विवेकपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूँ।

7. **परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा एवं नहीं सहेगा राजस्थान** जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में हुआ परिवर्तन, राजस्थान को अस्थिरता और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर ले जाकर विकसित, शिक्षित व खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेगा।

8. चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किये गये वादे वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र का अहम हिस्सा हैं। इसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब खुशहाली, समृद्धि और मजबूती के साथ **आपणो अग्रणी राजस्थान** का संकल्प जमीन पर साकार होगा।

9. इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजातशत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. श्री भैरोसिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार **पंडित दीनदयाल उपाध्याय** के दर्शन और विचारों पर आधारित **अंत्योदय योजना** को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालान्तर में अलग–अलग रूप में देशभर के प्रदेशों में लागू की गई।

10. माननीय भैरोसिंह जी के गरीब कल्याण के मौलिक विचारों को देखते हुए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने इसीलिए भैरोसिंह जी को **भारत के रॉकफेलर** की संज्ञा दी थी।

11. यह वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। अटल जी ने देश में ना केवल सुशासन की नींव रखी अपितु सड़क जोड़ो और नदी जोड़ो जैसी विशाल संकल्पनाओं को मूर्त रूप देकर भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी किया। हमारी सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री भैरोसिंह शेखावत के पदचिन्हों पर चलते हुए इनके विचारों के प्रति कटिबद्ध रहते हुए **लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय** को साकार करेगी।

12. हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जायेगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल के आखिरी समय में, बिना

बजटीय प्रावधानों के, आनन–फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जायेगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छान–बीन के उपरान्त ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर, ठोस एवं व्यावहारिक नये रूप में, जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जायेगा। इससे लोकतंत्र का असली उद्देश्य–**जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन** सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवाकार्य सुनिश्चित हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण !

13. विगत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों, अदूरदर्शी निर्णयों तथा आर्थिक कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्षों में राजस्थान को **आर्थिक आपातकाल** की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान पुनः **बीमारू और सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य** की श्रेणी में आ गया है।

14. आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश का कर्ज 5.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया है जो वर्ष 2019 में महज 3.39 लाख करोड़ रूपए था। वहीं वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति कर्जभार अड़तीस हजार सात सौ बयासी (38,782) रुपये से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में सत्तर हजार आठ सौ अड़तालीस (70,848) रुपये, यानी करीब दोगुना हो गया है।

15. विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में **ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस** के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए **राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स** की स्थापना की जायेगी जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

16. विगत 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आमजन किसान विद्युत कटौती का लगातार दंश झेलने को मजबूर रहे। आमजन में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ होती रही।

17. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की प्रदेश के डिस्कॉम को आर्थिक सम्बलता देने के लिए शुरू की गई उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 70 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से गत कांग्रेस राज के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण फिर से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये के पार कर गया है।

18. किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जाने के टर्नकी प्रोजेक्ट, विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला धुलाई और निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से महंगी दरों पर बिजली खरीद में गत सरकार के कार्यकाल में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा।

19. विगत सरकार के बढ़े हुए टीएंडडी लोस को नियंत्रित करके तथा **गैर जीवाश्म स्त्रोत वाली अक्षय ऊर्जा** को प्रोत्साहित कर राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। गत सरकार द्वारा घाटे में धकेले गये डिस्कॉम्स के आर्थिक हालात को विशेषज्ञों के परामर्श तथा कुशल प्रबंधन द्वारा सुधारकर नागरिकों, उद्योगों एवं किसानों को **गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति** सुनिश्चित की जायेगी।

20. हमारी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए **मॉनिटरिंग कमेटी का गठन** किया जायेगा। गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है, जो आपणो अग्रणी राजस्थान में उल्लेखित संकल्प पत्र में भी झलकता है। हमारी सरकार का **हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी** मुख्य ध्येय रहेगा।

21. हमारी सरकार जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर जनता दरबार के माध्यम से प्रभावी जनसुनवाई सुनिश्चित की जायेगी और आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्रशासन की पहली इकाई पर ही किया जायेगा।

22. हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इन्दिरा रसोई के स्थान पर अब श्रीअन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्रीअन्नपूर्णा रसोई में अब श्रीअन्न (मिलेट) को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्रीअन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई–बहिनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल पायेगा।

23. मुझे यह बताते हुए अत्यन्त खुशी है कि हमारी सरकार ने गरीब वर्ग की माताओं–बहनों के प्रति अपने संकल्प को पूरा करते हुए **1 जनवरी, 2024 से मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर** देने की घोषणा को मूर्त रूप दे दिया है। हमारी सरकार महिलाओं को सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तीकरण के लिए कटिबद्ध है।

24. राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** की राशि को दोगुना कर अब **12 हजार रुपये प्रतिवर्ष** करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।

25. गेहूं उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों की फसल का सही दाम सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित **गेहूं की एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर 2700 रु. प्रति क्विंटल** पर गेहूं खरीदने की योजना बनायेगी।

26. भारत विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा यानी श्रीअन्न (मिलेट) उत्पादन करने वाला देश है। इसमें भी राजस्थान देश में सिरमौर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय पोषक अनाज श्रीअन्न (मिलेट) वर्ष घोषित किया गया है। इस मिलेट–क्रांति के फलस्वरूप अब हमारे ज्वार–बाजरे को देश दुनिया में सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न के रूप में पहचाना जाने लगा है।

27. गत सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी को लेकर बड़े–बड़े दावे किये गये। कल्ला कमेटी बनाई गई, कृषकों की ऋणमाफी हेतु वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कही गई, लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए किसानों की कर्जमाफी के स्थान पर 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क और नीलाम कर दीं। अत्यन्त दुख का विषय है कि विगत सरकार की इस दोषपूर्ण कृषक नीति के कारण हमारे कई किसान भाई आत्महत्या करने तक को मजबूर हुए। किसान भाइयों के हितों की रक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं, उनको बिना विलम्ब किए उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा देने के लिए **व्यावहारिक मुआवजा नीति** निर्धारित की जायेगी ।

28. किसान भाइयों को खाद–बीज से लेकर बाजार तक किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रदेश में सुगम व्यवस्था तैयार की जाएगी। उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए **फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स** का गठन किया जाएगा।

29. पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) की डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन इस पर गत सरकार ने ठोस कार्य करने की बजाय इस परियोजना पर केवल राजनीति करने का काम किया। गत कांग्रेस सरकार द्वारा 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 170 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) को **वर्ष 2051** तक पूरा करने की बात कही गई थी, जो इस बात का द्योतक है कि सरकार 28 वर्षों तक इस योजना को लटकाना, भटकाना चाहती थी। इतने लंबे अरसे में तो दो–दो पीढियां तक बदल जाती हैं।

30. हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवनरेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर त्वरित गति से किया जायेगा। अब राजस्थान व मध्यप्रदेश, दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से **ईआरसीपी के संबंध में एमओयू** कर परियोजना को शीघ्र–अतिशीघ्र मूर्त रूप दिया जाना आसान होगा।

माननीय सदस्यगण !

31. विगत सरकार के समूचे कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभावान युवाओं का भविष्य अंधकारमय बन गया। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि एक भी भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक और पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न नहीं हो सकी। पेपर लीक घोटालों के मुख्य सरगनाओं को गत सरकार पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं में निराशा, असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त रहा।

32. **हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एसआईटी का गठन कर दिया है।** साथ ही अब **भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों से** करवाने तथा नकल माफियाओं के खिलाफ **केस ऑफिसर स्कीम** के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। हमारी सरकार **भ्रष्टाचार और माफिया राज का अंत** करने के लिए संकल्पशील है।

33. प्रदेश के युवाओं में हताशा और अवसाद के कारण आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय हैं। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से उनको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाने एवं उनकी ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में **युवा साथी केन्द्र** स्थापित किये जायेंगे।

34. हमारी सरकार प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को पूर्णतः आश्वस्त करती है कि प्रदेश में अब ना तो नौकरियों की लूट होगी और ना ही पेपर लीक होगा। **विद्यार्थियों को केजी से पीजी यानी प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** देने की गारंटी सरकार के संकल्प पत्र में निहित है, जिसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा।

35. भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस शांतिप्रिय प्रदेश में **कानून का शासन सुनिश्चित** करने में यह सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस क्रम में सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही अहम निर्णय लेते हुए **एक्शन मोड पर कार्य** शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप लंबे समय से फरार घोषित करीब 10 हजार अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही की गई है।

36. **पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण विगत 5 वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। विभिन्न विभागों में यथा–जल जीवन मिशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सोना एवं नकदी की बरामदगी, बायोफ्यूल प्राधिकरण जैसे हर विभाग में भ्रष्टाचार को शह मिली। प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन उस पर अंकुश लगाने की बजाय राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार की सीबीआई को अनुसंधान की सामान्य स्वीकृति न देने जैसे अनुचित निर्णय किए। जिससे विदित है कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने की कोई मंशा नहीं थी। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। एसीबी की जांच में सजा योग्य पाए गए प्रकरणों में भी पूर्ववर्ती सरकार ने न तो कोई ठोस कार्यवाही की और न ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की।**

37. **हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति से निर्णय लेते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई द्वारा अनुसंधान की शक्तियां बहाल कर दी हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए आगे भी ठोस एवं कड़े निर्णय लिए जाएंगे।**

38. राजस्थान में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रदेश में परिशांति कायम करने के लिए **एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन** किया गया है तथा प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए **साइबर सुरक्षा**

रणनीति तैयार कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु कवायद शुरू कर दी गई है।

39. राजस्थान में गत सरकार में महिला उत्पीडन एवं दुष्कर्म के मामले बड़े पैमाने पर सामने आए, जिससे राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में देशभर में पहले पायदान पर रहा। फलस्वरूप वीरों और विभूतियों की यह गौरव भूमि बार–बार कलंकित एवं शर्मसार हुई। हमारी मुख्य प्राथमिकता मातृशक्ति को समुचित सुरक्षा देकर प्रदेश का ऐतिहासिक मान–सम्मान और गौरव पुनः लौटाना है।

40. राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में **एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन** को पूरी मजबूती और मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे।

41. **हमारी सरकार घुमन्तु समुदाय के आवश्यक दस्तावेज जैसे–वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र आदि बनाने के लिये शिविर लगायेगी। उक्त समुदाय के परिवारों के लिये आवासीय पट्टे, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी ।**

42. **हमारी सरकार अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के लिये आरक्षित सभी सरकारी पदों को प्राथमिकता से भरेगी । हम केन्द्र सरकार के साथ मिलकर नमस्ते योजना के अन्तर्गत सभी मैनुअल स्कैवेजिंग से जुडे हुए मजदूरों के पुनः रोजगार के लिये प्रशिक्षण अथवा स्वरोजगार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेंगें ।**

माननीय सदस्यगण !

43. मैं इस अवसर पर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सबको साथ लेकर विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा तथा उनका मान–सम्मान बनाये रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रदेश में सबको साथ लेकर **गांधी जी के राम राज्य और सुराज की संकल्पना** को मूर्तरूप देगी। प्रदेश में कानून के शासन और सुशासन को मजबूती के साथ स्थापित किया जायेगा।

44. विगत कांग्रेस सरकार ने अपने बजट भाषण वर्ष 2019–20 के पैरा 79 में अक्टूबर 2022 तक **बाड़मेर रिफाइनरी** को पूरा करने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य है कि गत सरकार की लेटलतीफी एवं इच्छाशक्ति के अभाव के कारण आज तक रिफाइनरी मूर्त रूप लेकर प्रारम्भ नहीं हो पाई है तथा इस मूल परियोजना की लागत 37 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर अब 75 हजार करोड़ रुपये को पार कर गई है।

45. हमारी सरकार विशेषज्ञों की मदद से बाड़मेर रिफाइनरी के पूरे प्रोजेक्ट की नई सिरे से समीक्षा कर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर करीब 72 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर, बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के निर्माण में तेजी लाएगी।

46. राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की **विकसित भारत संकल्प यात्रा** 16 दिसंबर 2023 से शुरु होकर 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक राज्य में हजारों कैम्प आयोजित हो चुके हैं जहां पर विभिन्न शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को केंद्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर और वंचित पात्रताधारी लोगों का हाथों–हाथ पंजीकरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

47. मेरा सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि **विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रीय प्रयास** है, किसी राजनीतिक दल का कार्य नहीं, यह एक पवित्र कर्तव्य है। इसमें विकसित राष्ट्र निर्माण के वृहद उद्देश्य के साथ विकसित राजस्थान के ध्येय को सामने रखकर सभी प्रदेशवासियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

48. केन्द्र सरकार द्वारा **वर्ष 2025 तक हर घर में नल से जल** पहुंचाने के उद्देश्य से **जल जीवन मिशन योजना** संचालित की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य ही रहा कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों, घटिया सामग्रियों और टेलरमेड टेंडरों के माध्यम से गत सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल सका। इस महत्वाकांक्षी योजना की रैंकिंग में राजस्थान देश में सबसे निचले यानी 33वें पायदान पर पहुंच गया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर जहां एक ओर प्रदेश की जनता को योजना का लाभ दिलवाया जायेगा वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन योजना में गत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और शिकायतों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

49. मरुप्रदेश राजस्थान में देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए **भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बोर्ड गठित** करेगी तथा अन्य जल प्रदाय योजनाओं के कार्य को भी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी।

माननीय सदस्यगण !

50. गत सरकार द्वारा बिना कार्ययोजना और बिना पर्याप्त बजट के प्रदेश में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं कई मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर दी गई परन्तु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता व आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण इनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाई। अधिकांश महाविदयालय और विदयालय या तो कागजों पर या किराये की बिल्डिंग पर ही संचालित रहे। निजी विश्वविद्यालय खोलने की होड़ ने प्रदेश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा दिया। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि इसी सदन में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रीमंडल से अनुमोदित निजी गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर का प्रस्तुत विधेयक वापिस लेना पड़ा।

51. गत सरकार दवारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मात्र साइन बोर्ड बदलकर कथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूप में प्रारम्भ करने का कार्य किया गया। इन विद्यालयों में ना तो अंग्रेजी माध्यम प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित किये गये और ना ही विद् यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण किया गया और ना ही आवश्यक बजटीय प्रावधान किये गये। प्रदेश में इस अव्यावहारिक निर्णय का आम जनता, शिक्षकों और शिक्षाविदों की ओर से व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ। इतना सब होने पर भी सरकार विद्यार्थियों को अधरझूल में छोड़कर अनिर्णय की स्थिति में बनी रही। हमारी सरकार इन विद्यालयों की समीक्षा कर विद्यार्थी हित सर्वोपरि रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेगी ।

52. राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है तथा दूध उत्पादन में राजस्थान देश में अव्वल है। गत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा संचालित **पशु बीमा योजना** को बंद कर दिया था जिसे **लंपी वायरस** के प्रकोप के बाद मजबूरीवश अंतिम वर्ष में आधे अधूरे ढंग से लागू किया। फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में पशु बीमा योजना का लाभ पशुपालकों को नहीं मिल सका। सरकार लंपी महामारी के दौरान पशु चिकित्सा प्रबंधन में पूर्णतया विफल रही तथा काल कवलित पशुधन के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दे पाई।

53. गत सरकार दवारा प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की गई थी। दुर्भाग्य से यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं हो सकी जो इस बात का प्रमाण है कि गौधन की सार–संभाल के प्रति भी सरकार निष्क्रिय और असंवेदनशील रही। हमारी सरकार **गौमाता के संरक्षण और संवर्धन हेतु नई नीति** बनायेगी।

54. हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा सभी को आवास (**हाउसिंग फॉर ऑल**) सुनिश्चित करने हेतु देशभर में **प्रधानमंत्री आवास योजना** संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रताधारी लाभार्थियों के आवेदन भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गये थे।

55. हमारी सरकार जहां इन वंचित लाभार्थियों को उनका हक दिलवाएगी वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा कर **बनते घर–पूरे होते सपनों** को साकार करेगी। हम पीएम आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे तथा वह समाज में गरिमापूर्ण और सम्माजनक जीवन का हक प्राप्त कर सके।

56. हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम राजस्थान में मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन है कि ''हम भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को निरंतर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्यान नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर है।''

57. गत सरकार द्वारा '**राइट टू हेल्थ**' के नाम पर फौरी तौर पर मात्र औपचारिकता की गई जिसका चिकित्सकों और निजी अस्पतालों द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। अब हमारी सरकार ''**सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया**'' के ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। चिकित्सकों और निजी अस्पतालों को विश्वास में लेकर सही मायने में प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी।

58. गत सरकार द्वारा केन्द्र की **आयुष्मान योजना** को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार ''**सभी को स्वास्थ्य सेवाएं**'' सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब चिरंजीवी

योजना की समीक्षा करेगी और आयुष्मान योजना को जन केन्द्रित बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

59. केन्द्र सरकार द्वारा **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र योजना** के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अब **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आरोग्य मंदिर जन स्वास्थ्य की धुरी के रूप में कार्य करते हुए रोग उपचारात्मक सेवाओं के साथ प्रिवेंटिव एवं प्रमोटिव हैल्थ सर्विस भी उपलब्ध करवाएंगे। जिससे आमजन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो। यहां आमजन को बारह प्रकार की निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ योगा एवं वैलनेस गतिविधियों का संचालन करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

60. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशभर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए **प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र** की स्थापना की अनूठी पहल की है। प्रदेश में भी ऐसे 350 नए जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ताकि नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिल सके।

61. हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखकर **प्रतिवर्ष हर ब्लॉक में दो स्वास्थ्य मेलों** के आयोजन का संकल्प लिया है। इन मेलों में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जागरूक किया जायेगा।

62. राजस्थान प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण **मेडिकल टूरिज्म** की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी सरकार प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर 2 मेडिसिटी स्थापित करेगी। भारत सरकार के **हील इन इंडिया** कार्यक्रम की तर्ज पर राजस्थान में **हील इन राजस्थान** कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

63. हमारी सरकार **वन डिस्ट्रिक्ट– वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट – वन नर्सिंग कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट–वन डायलिसिस केन्द्र एवं वन ब्लॉक – वन डायग्नोस्टिक सेंटर** स्थापित कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।

माननीय सदस्यगण !

64. हमारी सरकार **लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय–प्रण अंत्योदय** के मूलमंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को **नीतिगत दस्तावेज** का रूप दिया गया है। हमारे संकल्प पत्र में खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, आरोग्य प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून–व्यवस्था, गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग तथा सुदृढ आधारभूत संरचना के लिए प्रतिबद्धता दर्शायी गई है। आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की इन प्राथमिकताओं को अक्षरशः धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

65. जन आस्था से जुड़े पर्वतों पर हो रहा अवैध खनन हमारे लिए चिंता का विषय है। इससे जहां एक ओर कानून–व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है, वहीं आमजन में रोष है। अवैध खनन से पर्यावरण को खतरा होने से **पारिस्थितिकी संतुलन** पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। हमारी सरकार **अरावली, आदिबद्री एवं कनकांचल** सहित प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को सख्ती से रोकेगी ।

66. राज्य में बढ़ता प्रदूषण हम सबके लिए गहन चिंता का कारण है। **राजस्थान ग्रीन वॉर रूम** की स्थापना कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्थक प्रयास किये जाएंगे।

67. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि देश के सभी शहर **स्मार्ट सिटी** बनें। इसके लिए प्रदेश के **4 शहरों उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा** को केन्द्र की **स्मार्ट सिटी मिशन योजना** के तहत चयनित कर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी क्रम में नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने **अटल नवीनीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत योजना)** का शुभारम्भ किया लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार इस परियोजना के प्रति उदासीन रही। फलस्वरूप आमजन को केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। हमारी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का विस्तार कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है।

68. सड़क मार्ग के साथ–साथ सुरक्षित रेलमार्गों के विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनों के संचालन की दिशा में भी केंद्र सरकार ने दूरदर्शी विजन के साथ काम किया है। **वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा इलेक्ट्रिक हाइवे** के संचालन से लंबी दूरी का सफर अब कम समय में

सुगमतापूर्वक तय होने जा रहा है। राजस्थान को भी विगत दिनों में वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है।

69. हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उन्हें आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बेहतर माहौल देने के लिए नीतिगत फैसले लेगी। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मान–सम्मान बढ़े और उन्हें सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिलें।

70. भारत ने हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक के सबसे अधिक 107 पदक जीते हैं। राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने भी मैडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसी प्रकार की खेल प्रतिभाओं को **ओलम्पिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ और अन्य राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं** के लिए विशेष रूप से कार्य योजना तैयार की जायेगी।

71. हमारी सरकार द्वारा प्रदेशभर में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए **नशा मुक्त राजस्थान** की संकल्पना की है। यह सुखद संयोग है कि इस बार सदन में अनेक नये युवा सदस्य चुनकर आये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर युवा विधायकों का आहवान करता हूं कि प्रदेश की युवा शक्ति को नशे से दूर रखने की दिशा में आप अपने–अपने क्षेत्रों में नशा मुक्त राजस्थान अभियान को सशक्त करें ।

माननीय सदस्यगण !

72. राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना का विकास हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने **दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना** शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में खुशखेडा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर–पाली–मारवाड औद् योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादों के सुगम एवं त्वरित आवागमन के लिए **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब** एवं **नए एक्सप्रेस वे** तथा रेल कॉरिडोर के निकट **इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर** की स्थापना की जाएगी।

73. जेम्स, ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट और वस्त्र आदि के निर्यात में राजस्थान की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान है। हमारी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए **स्पेशल इकोनोमिक जोन** विकसित करेगी। **नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी** तैयार की जाएगी एवं **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की अपार सम्भावनाओं की देखते हुए **स्टार्ट अप को प्रोत्साहित** किया जाएगा।

74. सर्विस डिलीवरी सिस्टम, विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रोजमर्रा की जरूरतों में **सूचना प्रौद्योगिकी** का उपयोग विगत वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार प्रदेश में **ई–गवर्नेंस एवं एम–गवर्नेंस** के साथ **डिजिटल पेमेंट सिस्टम** को बढ़ावा देगी। **आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस** का उपयोग कर सुशासन में तकनीक के उपयोग को विस्तार दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न विभागों में ई–गवर्नेंस परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं मशीन लर्निंग आधारित तकनीक के उपयोग को बढावा दिया जायेगा एवं साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

75. श्रमिकों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए श्रमिकों का **ई–श्रम पोर्टल** पर शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। हमारी सरकार **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना** के माध्यम से श्रम कल्याण की दिशा में संकल्पशील रहेगी।

76. पर्यटन क्षेत्र में विकास की राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भक्ति, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की धरा राजस्थान के कण– कण में ऐसी गाथाएं रची–बसी हैं, जो देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां के मेले, तीज–त्योहार लोक संस्कृति, किले, महल, बावड़ी और पुरासम्पदा विश्व भर में विख्यात हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार **पर्यटन विकास के लिए विशेष कार्ययोजना** बनाएगी।

77. राजस्थानी व्यंजनों का जायका देश–दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पर्यटकों में भी इन व्यंजनों के प्रति खासा चाव है। इसे ध्यान में रखते हुए **वार्षिक राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय फूड उत्सव** आयोजित किए जाएंगे जिसमें श्रीअन्न को प्राथमिकता दी जायेगी। इन उत्सवों के माध्यम से श्री अन्न निर्मित विभिन्न राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू सुदूर देशों तक पहुंचेगी।

78. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि राज्यों के विकास के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से राज्यों में विकास की

नई बुनियाद रखी, ताकि राज्यों का सतत्, निर्बाध और समावेशी विकास सुनिश्चित हो।

79. नई सरकार की नीति और नीयत एकदम साफ है। हम **विकसित भारत 2047** के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है।

80. हम बेहतर तरीके से कुशल एवं स्मार्ट सुशासन, नैतिक मूल्य व्यवस्था, गांधी जी का राम राज्य एवं सुराज, विधि का शासन, समावेशी एवं सतत् विकास, प्रशासन में जवाबदेही, प्रभावशील दक्षता एवं पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस, ई–गवर्नेंस, एम–गवर्नेंस, **मिनिमम गवर्नमेंट– मेक्सिमम गवर्नेंस** के साथ संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे।

81. इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ–साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगेः–

1. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय सदस्यगण !

82. भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परम्परा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है। राजस्थान प्रदेश भी अपनी परम्परा और विरासत के लिए विश्वविख्यात है। इस धरोहर को सहेजकर हम आस्था और संस्कृति के संरक्षण के साथ विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेंगे।

83. सर्वलोकहितकारी राष्ट्र राज्य का जो स्वरुप महर्षि चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया है उस पर चलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चाणक्य ने कहा है कि–

प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितम् राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा का अपना प्रिय (स्वार्थ) में राजा का हित नहीं है, प्रजा का प्रिय में ही उसका हित है।

वन्दे मातरम् – जय हिन्द जय भारत